महिला कैदियों का यौन-शोषण

*615. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश के सभी राज्यों की जेलों में महिला कैदियों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत वर्षों के दौरान महिला अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) कितने राज्यों में अलग महिला कारावासों की स्थापना की गयी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कारावासों में विचाराधीन महिला कैदियों के गर्भवती होने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में तथ्यों का पता लगाया है; और

(च) कितने कारावासों में महिला कैदियों के यौन-शोषण के मामले सामने आये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.1997 की स्थिति अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में 7848 महिला कैदी थीं।

(ख) विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तार की गई महिलाओं से संबंधित उपलब्ध सूचना निम्नप्रकार है:

वर्ष	भा.द.सं.	एस.एल.एल.	जोड़
1993	95,533	2,52,168	3,47,701
1994	96,082	2,39,554	3,35,636
1995	1,06,079	2,29,561	3,35,640

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि, भा.द.सं. के मामलों में संलिप्त महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु विशेष और स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत मामलों में संलिप्त महिलाओं की संख्या में कमी आई है।

(ग) उन जेलों को छोड़कर जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सामूहिक होती हैं, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुछ जेलें केवल महिलाओं के लिए ही हैं।

(घ) से (च) चूंकि "जेल" राज्य का विषय है, इसलिए प्रश्न में उल्लिखित घटनाओं के ब्यौरे केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

Installation of new Naphtha project

*616. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry have plans to instal 12,000 MW of power capacity using Naptha as fuel;

(b) whether it is also a fact that the total requirement of Naptha will have to be imported; and

(c) if so, what will be the impact of this on our oil import?

THE MINISTER OF POWER (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): (a) In order to meet the energy shortage in the short run, the Government had allocated liquid fuel for about 12,000 MW of projects to the various States. As per the revised liquid fuel policy recently announced, the existing ceiling would apply only to naphtha and the states would be free to contract for new power projects based on F.O. and non-traditional fuels like condensate and orimulsion.

(b) and (c) The total import of fuel for these naphtha based power projects will depend upon the overall demand, including sectors other than power and also the domestic supply position. It is not expected that all the liquid fuel based projects would materialise and it has been assessed that only about 6000 MW would be commissioned during the 9th Plan period. If all the naphtha based projects for which linkages have been issued so far, are commissioned, it is estimated that the annual import of naphtha would be